



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

संख्या 16]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 6, 1996 / अवाक्ष 15, 1918

No. 16]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 6, 1996/ASADHA 15, 1918

इस भाग में खिल्प पृष्ठ मध्योदयी जारी है जिसमें नियम अथवा नियन्त्रण के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उत्तर-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गये आदेश और अधिनियमों
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administration of Union
Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 1996

आ. अ. 73.—यह निर्वाचन आयोग का गमाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट
गोदा शिक्षान्मुख्य के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने
विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रयोक्ता अधिकारी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अनेक नियमों
उपर मरणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्यवस्था का नेतृत्व दायित्व करने में व्यक्त रहा है।

अब यह, उक्त अधिकारियों द्वारा आयोग द्वारा सम्मुक्त मूलना दिए जाने पर भी उक्त असमिकाना के लिए या तो कोई कारण
अथवा स्पष्टोकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अस्पष्टों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग
का यह समाधान ही गया है कि उसके पास उक्त असमिकाना के लिए कोई पर्याप्त कारण या आवाजान्त्रिक नहीं है।

अब अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुवर्ण में नीचे की नामों के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट
व्यक्तियों को सम्मद के किसी भी मूलन के या किसी रजिस्ट्रेशन-क्षेत्र की विधान सभा अवधान परिषद के मूलन जैसे जाने
ओर होने के लिए इस आदेश की नामीक्र से तीन वर्ष की कानूनीधि के लिए प्रतद्वारा निर्हित घोषित करना है।

सारणी

क्रम सं. निर्वाचन का विवरण

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन लड़ने वाले अन्य निर्गता का कारण
की क्रम सं. और नाम थियों के नाम और पाने

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गोवा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए 20-पोन्डा साधारण निर्वाचन		मेल्ला दशकीर मुल्ला ओ. निर्वाचन व्ययों का कोई पी. ए., खाडेपार, गोवा भी लेंद्वा दाखिल करने में असफल रहे।	

[सं० 76/गोवा-वि० स०/95]

आषेश ये,
बाबू राम, सचिवELECTION COMMISSION OF INDIA
ORDER

New Delhi, the 7th June, 1996

O.N. 73.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Goa Legislative Assembly specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament for the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order ;—

TABLE

No.	Particulars of Election	Sr. No. & Name of the Assembly Constituency	Name & Address of the contesting candidates	Reasons for disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Elections to the Goa Legislative Assembly	20—Ponda	Mulla Dashkir Mulla OPA, Khandepar, Goa.	Failed to lodge any account of election expenses

[No. 76/GOA-LA/95]

By order,
BABU RAM, Secy.

नई दिल्ली, 19 जून, 1996

प्रा.प्र. 74:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की जागा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने क्षा, भारत निर्वाचन आयोग, मणिपुर राज्य सरकार के परामर्श में श्री.पी. शर्मा चन्द्र, प्राइ.ए.एम., आयुक्त प्रथम विशेष सचिव (मत्रिमण्डन) को मणिपुर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में, उनके कार्यभार छह

करने की तारीख से ग्रामके आदेशों तक, श्री जरनल सिंह के स्थान पर एतद्वारा नामित करता है। उल्लेखनीय मन्त्रिवालय में निर्वाचन आयोग के अधीन निर्वाचन संबंधी कार्यों के विभाग में सरकार के सचिव के रूप में भी पदाधिकार किया जायेगा।

2. आयोग ने नोट किया है कि श्री शरत चन्द्र के पास आयुक्त और विशेष सचिव (मंत्रिमण्डल) का अतिरिक्त कार्यभार है आयोग मणिपुर राज्य में पूर्ण कालिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए जोर नहीं दे रहा है क्योंकि राज्य में दो से अधिक दीवान निर्वाचन-श्वेत नहीं हैं। जसे ही साधारण निर्वाचन संस्करण होते हैं, श्री पी. शरत चन्द्र को मध्यी और प्रत्येक अतिरिक्त कार्यभार में मुक्त कर दिया जाए और एक अनुपालन रिपोर्ट आयोग को भेज दी जाए।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मणिपुर के रूप में कार्य करते हुए श्री पी. शरत चन्द्र आयोग से पूर्व लिखित स्वीकृति लिए बिना उपर परा 2 में उल्लिखित कार्यभारों के अतिरिक्त मणिपुर सरकार के अधीन कोई अन्य कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे।

4. साधारण निर्वाचन के संस्करण अःने दर यदि श्री पी. शरत चन्द्र को उनके मध्यी अतिरिक्त कार्यभारों से मुक्त नहीं किया जाता या आयोग में पूर्व लिखित स्वीकृति लिए बिना उपर परा 2 में बणित कार्यभार के अलावा किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है या ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है तो वे इस आदेश की शर्तों के अनुसार, ऐसा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मणिपुर के पदधार से अपने आप हटा दिए गए समझे जाएंगे और किसी अलग आदेश को जारी नहीं किया जाएगा अथवा जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में ड्यूटी और काय के नथाकथित निवहन में उनके द्वारा की गई सभी या कोई कारबाई अप्राधिकृत, थोकाधिकार के बिना, नामित, अकृत और शून्य होंगी और वह स्वयम् अनुशासनात्मक कारबाई के भासी होंगे।

[सं. 154/मणि./96]

आदेश में,
के.पी.जी.कुट्टी, सचिव

New Delhi, the 19th June, 1996

O.N. 74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Manipur hereby nominates Shri P. Sharat Chandra, IAS, Commissioner and Special Secretary (Cabinet) as the Chief Electoral Officer for the State of Manipur with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Jarnail Singh. He will also be designated as Secretary to the Government in the department in the State Secretariat dealing with elections under the Election Commission.

2. The Commission has noted that Shri P. Sharat Chandra has additional charge of Commissioner and Special Secretary (Cabinet). The Commission is not insisting on a full-time Chief Electoral Officer in the State of Manipur as the State has not more than two Parliamentary Constituencies. As soon as a general election becomes imminent, Shri P. Sharat Chandra shall be divested of all and every additional charge and a compliance report sent to the Commission.

3. Shri P. Sharat Chandra while functioning as Chief Electoral Officer, Manipur, shall not hold, without the prior written approval of the Commission any additional charge, whatsoever, under the Government of Manipur over and above the charges mentioned in paragraph 2 above.

4. If Shri P. Sharat Chandra is not divested of all his additional charges as soon as a general election becomes imminent or is entrusted with or ordered to hold any additional charge of any kind whatsoever over the above the charge mentioned in paragraph 2 above, without the prior written approval of the Commission, Shri P. Sharat Chandra will stand removed from the office of the Chief Electoral Officer, Manipur from the date of assumption of any such additional charge in terms of this very order and no other order will, or need to, be issued. All and any action taken by him thereafter in the discharge of his duties and functions as the Chief Electoral Officer shall be unauthorised, without jurisdiction, non-est and null and void and he shall render himself liable to disciplinary action.

[No. 154/MR/96]

By order,
K. P. G. KUTTY, Secy.

